PAPERS LAID ON THE TABLE - Contd

I. **Notification of the Ministry of Social Justice and Empowerment.**

II. **Report (1995-96 and 1996-97) of the National Commission for Backward Classes, New Delhi and related papers.**

III. **Report and Accounts (1999-2000) of the Institute for the Physically Handicapped, New Delhi and related papers.**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): Sir, I lay on the Table:-

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Social Justice and Empowerment Notification G.S.R.579(E) dated 3rd August, 2001 publishing the Board of the Trust Regulations, 2001, under section 36 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999. [Placed in Library. *See* No. L.T. - 4187/01]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

(i) (a) Annual Report of the National Commission for Backward Classes, New Delhi, for the years 1995-1996 and 1996-1997 under section 15 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993.

(b) Memorandum of Action Taken on the advices tendered by the National Commission for Backward Classes.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library. *See* No. L.T. - 3907/01]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Institute for the Physically Handicapped, New Delhi, for the year 1999-2000, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library. *See* No. L.T.-3906/01]

SHORT DURATION DISCUSSION

Economic slowdown, fall in GDP rate and deteriorating financial condition of the country in the context of mid-term appraisal of Ninth Five Year Plan -- *Contd.*

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति जी, हम लोग अपने देश की आर्थिक दशा जो दयनीय होती चली जा रही है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। श्रीमन्, हमारे देश में इस समय औद्योगिक विकास दर में भारी कमी आ गई है और कृषि में बहुत ज्यादा कमी आ गई है। हम लोगों की स्थिति तथा हमारा जो आर्थिक ढांचा है वह एक बार तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी तरह से चरमरा गया है। बावजूद इसके कि माननीय वित्त मंत्री जी 7 प्रतिशत अपना सकल घरेलू उत्पाद करने का ऐलान करते रहे हैं हर बजट में जो भी उनके बजट हर साल आ रहे हैं और माननीय प्रधान मंत्री 9 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद को करना चाहते हैं इसकी विकास दर को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि वह केवल 5.2 प्रतिशत है और यह स्थिति केवल आज की नहीं है पिछले लगातार 5 सालों से गिरावट दर्ज हो रही है, हमारी विकास दर घरेलू सकल उत्पाद में घटती चली जा रही है। कृषि में जो स्थिति है, औद्योगिक क्षेत्र में जो स्थिति है वह और भी भयावह है। कृषि में 2000 में 0.7 प्रतिशत हमारी विकास दर रह गई और आज की तारीख में केवल 0.2 प्रतिशत उसकी विकास दर है। औद्योगिक क्षेत्र में भी जो हमारी औद्योगिक विकास दर 7.1 प्रतिशत थी वह अब 3.4 प्रतिशत रह गई है और इस समय तो वह 1.9 प्रतिशत है। दूसरी तरफ भी स्थिति बहुत खराब है। हमारा जो सार्वजनिक कर्जा है वह इस साल हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 70 प्रतिशत है। सकल घरेलू उत्पाद में हमारा सार्वजनिक कर्जा 70 फीसदी से भी अधिक हो जायेगा। इतना ही नहीं, जो हमारा वित्तीय घाटा है वह हमारा सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा हो जायेगा। अगर इन सारी चीजों को पूरे देश के परिदृश्य में देखते हैं तो पाते हैं कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, इनमें से साढ़े चार करोड़ नौजवान रजिस्टर्ड हैं और बाकी लोग अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, ऐसे लोगों की तादाद भी बहुत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इसको केवल पांच साल के प्रबंधन की कमी नहीं मानता हूं। जैसा कि माननीय प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा कि तीन साल के प्रबन्धन की कमी के कारण या आंकड़ों के हिसाब से या उसके घट-जोड़ के हिसाब से ऐसा हुआ है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। इसका बीज तो 1990-91 में पड़ गया था जब हमने यह तय कर लिया कि हम विश्व व्यापार संगठन के जरिये से उदारवाद लायेंगे, भूमंडलीकरण करेंगे, खुला बाजार करेंगे, यह उसी दिन निश्चित हो गया कि हमारी स्थिति ऐसी होती चली जायेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि 1990-91 में जो सब्जबाग दिखाये गये उस समय की सरकार द्वारा तो उस समय हमारे यहां के बुद्धजीवियों ने, उच्च मध्यम वर्ग ने, हमारे उद्योगपतियों ने, हमारे राजनेताओं ने, हमारे नौकरशाहों ने बड़े-बड़े कशीदें पढे इस योजना के लिए कि हम उदारवाद में आ रहे हैं, हम खुले बाजार में आ रहे हैं, अब हमारी तरक्की होती चली जायेगी, लेकिन आज वह भ्रम दूर